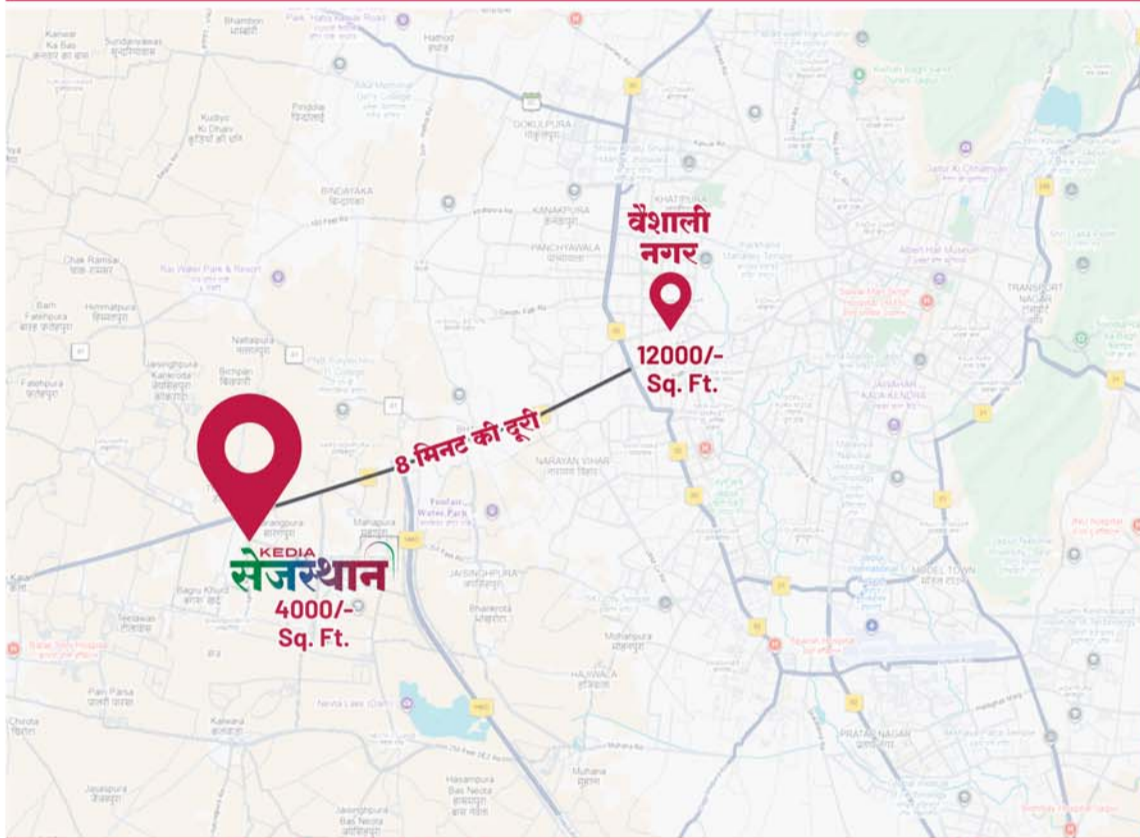


8 मिनट की दूरी पर  
8000/-/Sq. Ft. का फायदा

₹40000/- में फ्लैट!  
₹50000/- में कोठी!

## REAL VALUE • REAL GROWTH



उतने ही पैसे में तीन गुना बड़ा फ्लैट

## FIXED PRICE

PRODUCT TYPE	UNIT TYPE	SIZE	FIXED PRICE
WALK-UP APARTMENT	2 BHK (GF)	1350 Sq Ft	65 LACS
	3 BHK (SF)	1900 Sq Ft	75 LACS
	3 BHK (FF)	1900 Sq Ft	80 LACS
KOTHI	3 BHK BIG	2000 Sq Ft	1.05 CRORE
	4 BHK BIGGER	2325 Sq Ft	1.25 CRORE
	4 BHK BIGGEST	3200 Sq Ft	1.55 CRORE



अब हर महीने रेट बढ़ेगी!

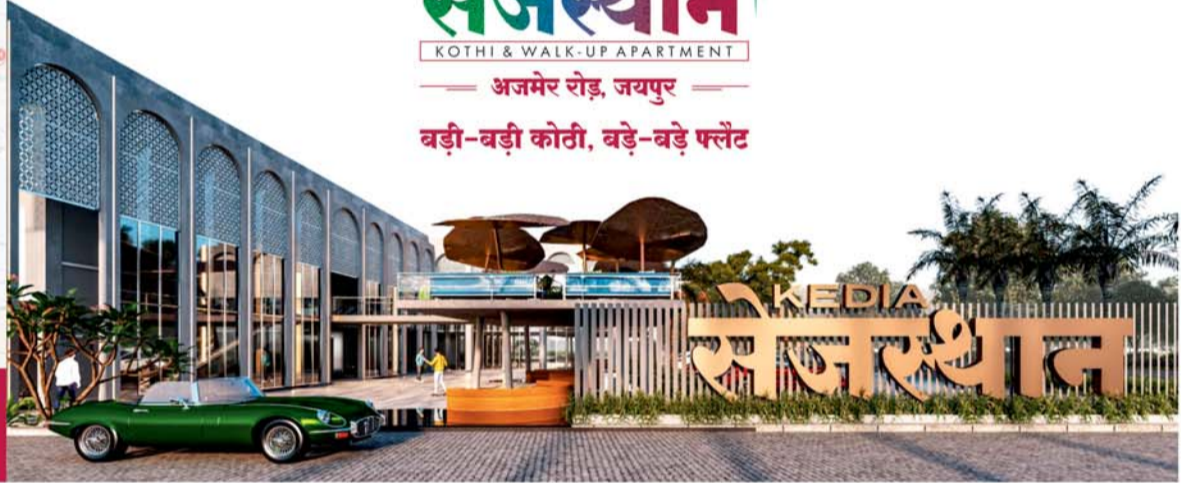


**KEDIA**  
**सेजस्थान**

KOTHI & WALK-UP APARTMENT

अजमेर रोड, जयपुर

बड़ी-बड़ी कोठी, बड़े-बड़े फ्लैट



KEDIA®

1800-120-2323  
78770-72737

घर के लिए

घर के खाने के लिए

info@kedia.com  
www.kedia.com

SCAN QR FOR  
• LOCATION  
• ROUTE MAP  
• SITE 360 TOUR  
• E-BROCHURE  
• WALKTHROUGH

आन्दोलन  
अशुद्ध के विरुद्ध

मिलावट में इस्तेमाल होने वाले  
खतरनाक तत्व  
और उनसे होने वाले नुकसान

**ब्रिक पाउडर**

- दिमागी विकास में कमी
- सांस लेने में दिक्कत
- बच्चों की ग्रोथ पर असर

**मेटानिल येलो**

- एलर्जी और स्किन रिश्कशन
- इम्युनिटी कमजोर होना
- फूड पॉइजनिंग का खतरा

**सिंथेटिक डाई**

- लीवर डैमेज
- किडनी पर बुरा असर
- पाचन संबंधी समस्याएं



KEDIA™  
**Pavitra**

सेहत से समझौता नहीं  
पवित्र मसाले ही सही!

CRYOGENIC GRINDING प्रोसेस से बने

**लाकाडोंग हल्दी पाउडर**

7-12% करक्यूमिन  
विश्व में सर्वाधिक करक्यूमिन  
वाली हल्दी

**लाल मिर्च पाउडर**

50,000+ SHU (तीखापन)  
तेजा, बेड़गी और लोंगी मिर्च  
का यूनिक मिश्रण

**धनिया पाउडर**

डबल पेरेंट धनिया  
एक्सपोर्ट क्वालिटी  
हाईएस्ट ग्रेड



FIXED PRICE

स्टिलर हो या कस्टमर:  
कॉल लगाओ, गाड़ी बुलाओ

1800 120 2727

सभी जिला मुख्यालयों पर Market Development Officer (MDO) हेतु आदेन करें।  
Email ID : hr@kedia.com | Call : +91 76888 44466

54000 + RETAILERS SUPERMARKETS ZEPTO WEBSITE WHATSAPP APP TOLL FREE

ORDER ON WEBSITE



ORDER ON WHATSAPP



ORDER ON APP



ORDER ON ZEPTO



T&C Apply



## ‘प्र.मंत्री मोदी ने “राष्ट्र के नाम संदेश” प्रसारित करने की परम्परा का दुरुपयोग किया’

विपक्ष का आरोप है कि प्र.मंत्री मोदी ने इस प्रसारण की सुविधा का बहाना पकड़कर एक पूर्णतया राजनीतिक भाषण दिया और विपक्ष को, विशेषकर कांग्रेस को बुरी तरह कोसा

## लोकसभा का सातवां सत्र समाप्त

—जाल खंबाता—  
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—  
नई दिल्ली, 18 अप्रैल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने शनिवार को अठारहवीं लोकसभा के सातवें सत्र का समापन करते हुए बताया कि सत्र को उत्पादकता लगभग 93 प्रतिशत रही। उन्होंने कहा कि 31 बैठकें हुईं, जिनका कुल समय 151 घंटे 42 मिनट था। केन्द्रीय बजट पर सामान्य चर्चा लगभग 13 घंटे चली, जिसमें 63 सांसदों ने भाग लिया। संविधान (131वाँ संशोधन) बिल, केन्द्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल और परिसीमन बिल

## ईरान में भी नेतृत्व में “पावर स्ट्रगल” ( सत्ता के संघर्ष ) साफ दिखने लगा है!

एक तरफ हैं, विदेश मंत्री अब्बास अराघची व राष्ट्रपति पेजेस्कियन, जो व्यवहारिक नर्म रुख के हिमायती हैं, दूसरी ओर हैं कट्टरपंथी, जो सुप्रीम कमांडर मोजतबा खामनेई और संसद के स्पीकर के समर्थक हैं, जिन्हें इरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर की पूरी बैकिंग भी प्राप्त है।

## लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने बताया कि इस सत्र की प्रोडक्टिविटी 93 प्रतिशत रही।

पर 16 अप्रैल से आठवें विशेष सत्र में 21 घंटे 27 मिनट तक चर्चा हुई, जिसमें 131 सांसदों ने भाग लिया। बिड़ला ने कहा कि संविधान संशोधन बिल पारित नहीं हो सका। सत्र के दौरान 12 सरकारी बिल पेश किए गए और 9 बिल पारित हुए, जबकि कुल 326 सार्वजनिक महत्त्व के मुद्दे उठाए गए। बिड़ला ने जानकारी दी कि भारत की राष्ट्रपति ने 28 जनवरी, 2026 को दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

—अंजन राँव—  
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—  
नई दिल्ली, 18 अप्रैल ईरान में कड़ा रुख अपनाते वालों और अधिक सूक्ष्म वार्ता रणनीति व संभावित सामान्यीकरण के पक्षधर नेताओं के बीच विभाजन है। ईरान की राज्य संरचना के विभिन्न स्तरों पर नेताओं के अलग-अलग रुख हैं। विदेश मंत्री अब्बास अराघची और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन नर्म रुख के पक्षधर माने जाते हैं। दूसरी ओर हैं, सर्वोच्च नेता मोजतबा खामनेई जो अभी अनुपस्थित हैं, और संसद के अध्यक्ष के समर्थक हैं, जो कट्टरपंथी हैं, संसद के स्पीकर ने पहले युद्धविराम वार्ता का नेतृत्व किया था। उन्हें ईरानी क्रान्तिकारी गार्ड्स कॉर्प्स (आईआरजीसी) का समर्थन प्राप्त है, जिसका आंतरिक सुरक्षा पर कड़ा नियंत्रण है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इस “पावर स्ट्रगल” के कारण ही एक बार तो घोषणा हुई कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सभी जहाजों के आवागमन के लिए खोल दी गई है। पर, शाम तक दूसरी घोषणा आई कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पुनः आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है, अमेरिका के ब्लॉकड के कारण। यह स्थिति और जटिल हो गई क्योंकि ट्रंप भी अपनी किसी बात पर दृढ़ता से नहीं टिकते। इसके अलावा ईरान में जमीनी संगठन की इकाइयों को अपने स्तर पर काफी निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। इसीलिए भारत के जहाज, जो तेल लेकर भारत आ रहे थे, पर, फायरिंग हुई और उन्हें बीच रास्ते में अपने जहाजों को रोक कर पीछे लौटने को मजबूर किया गया। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, तब भी नहीं जबकि ईरान व अमेरिका के बीच लड़ाई चरम पर थी।

—रेणु मिश्रल—  
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—  
नई दिल्ली, 18 अप्रैल। दो महत्वपूर्ण राज्य विधानसभाओं के चुनावों की पूर्व संघ्या पर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लोगों से सीधे बात करने और अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमला करने का अवसर मिला, जिन्होंने बिल को असफल कर दिया। यह भाषण प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुकूल बिल्कुल नहीं था। इसमें मॉडल आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए विपक्षी पार्टियों पर हमला किया गया। राष्ट्र के नाम संबोधन आमतौर पर गंभीर मामलों के लिए आरक्षित होता है, जैसे युद्ध, कोई आपात स्थिति, बड़े नीतिगत फैसले आदि। शाब्दिक यह पहला अवसर है, जब इसका इस्तेमाल विपक्षी

दलों पर व्यक्तिगत हमले करने के लिए किया गया। इस प्रकार, वे हमारी सबसे खराब अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं!! उन्होंने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लिए चुनावी प्रचार भाषण दिया, और एयर-वेक्स (प्रसारण) का दुरुपयोग किया। सभी सभ्य समाजों में एयर-वेक्स के निष्पक्ष आवंटन के नियम होते हैं, ताकि सभी राजनीतिक विचारों को बराबर समय मिले। इस मामले में प्रधानमंत्री को भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता। यदि वे विपक्षी पार्टियों पर हमला करने के लिए एयर-वेक्स का उपयोग करते हैं, तो विपक्ष को भी ठीक उसी समय अवसर मिलना चाहिए, ताकि वे जवाब दे सकें। प्रधानमंत्री का संबोधन महिला

आरक्षण बिल से संबंधित था, लेकिन परिसीमन और लोकतंत्र को दरकिनारा करने और संघीय ढांचे पर हमला करने के उनके प्रयास का उसमें कोई उल्लेख नहीं था। यह प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक नेता का राजनीतिक भाषण था, जिसे (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## ‘करौली जिला क्रिकेट संघ के चुनाव को लेकर खेल सचिव का फैसला तर्कसंगत नहीं’

हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि खेल सचिव 60 दिन के भीतर पुनः सुनवाई करके न्यायसंगत फैसला सुनाएं

—यादवेन्द्र शर्मा—  
जयपुर, 18 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट में करौली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अवैध और असंवैधानिक तरीके से चुनाव आयोजित कराए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश समीर जैन ने आदेश पारित किया है कि इस मामले में युवा मामलात और खेल विभाग के सचिव द्वारा पूर्व में दिए गए आदेश तर्कसंगत नहीं हैं। उन्होंने सचिव को पुनः सभी संबंधित पार्टी/क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से चुनाव आयोजित करने से संबंधित शिकायतों और आपत्तियों की सुनवाई करते हुए 60 दिन के भीतर नए आदेश पारित करने को कहा है। इस मामले में याचिकाकर्ता करौली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में कहा गया कि, एडहॉक कमेटी ने चुनाव के नोटिस अवैध तरीके से जारी किए थे, क्योंकि उस समय खेल सचिव के समक्ष अपील दायर की हुई थी। परंतु तत्कालीन खेल सचिव ने करौली जिला क्रिकेट संघ के सदस्यों के पक्ष को भी सुनना उचित नहीं समझा। बाद में खेल सचिव के फैसले पर 11 जून 2025 को हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। एस.एस.होरा और उनके सहायक अधिवक्ता अप्रति गुप्ता पैरवी के लिए पेश हुए थे। यह मामला करौली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव आयोजित करने से संबंधित है। एसोसिएशन को 22 मई 2025 को एडहॉक कमेटी द्वारा चुनाव आयोजित

## एसआई भर्ती 21 के चयनित अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

जयपुर, 18 अप्रैल। हाईकोर्ट की खंडपीठ के 859 पदों की एसआई भर्ती: 2021 को रद्द करने के 4 अप्रैल 2026 के फैसले के खिलाफ चयनित एसआई अजीत सिंह राजपूत व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी है। एसएलपी में चयनित एसआई ने

## उन्होंने हाई कोर्ट की खंडपीठ के फैसले को निरस्त करने का आग्रह किया।

एसआई भर्ती: 2021 को बरकरार रखते हुए खंडपीठ के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया है। चयनित एसआई का कहना है कि पूरी भर्ती को ही रद्द करना गलत है और जिन अभ्यर्थियों का चयन वैध तरीके से हुआ है, उन्हें नौकरी में बरकरार रखा जाए। लेकिन जिन्होंने नकल और पेपरलोक के जरिए गडबडी से परीक्षा पास की है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ऐसे में कुछ लोगों की गलती की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## डीएमके ने अपने सांसद से राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पेश करवाया

महिला आरक्षण बिल रोकने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराने की कोशिश का जवाब देने के लिए डीएमके ने यह पहल की

—श्रीदंड झा—  
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—  
नई दिल्ली, 18 अप्रैल। जहाँ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में यह रेखांकित करने की कोशिश की कि विपक्षी पार्टियों ने महिला आरक्षण को रोक रखा है, वहीं ड्रमुक ने सरकार की इस नैरेटिव का मुकाबला करने की पहल की है।

भाजपा नेतृत्व वाली संविधान के 131वें संशोधन बिल के संसद परीक्षण में विफल होने के कुछ समय बाद, ड्रमुक के सांसद विल्सन ने राज्यसभा में एक निजी सदस्य बिल पेश किया, जिसमें प्रस्ताव किया गया कि लोकसभा की वर्तमान 543 सीटों के आधार पर अगले चुनाव से महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाए, बिना किसी सीट वृद्धि, परिसीमन या नए या पुराने जनगणना डेटा के।

डीएमके सांसद विल्सन ने राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया और अगले आम चुनाव में सीटों की संख्या में वृद्धि किए बिना महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा। यह विधेयक महिला आरक्षण पर विपक्षी पार्टियों की स्थिति को सामने लाने वाला पहला विधायी कदम है। हालांकि, सत्रावसान के कारण इस पर चर्चा नहीं हो पाई। यह विधेयक संविधान संशोधन का प्रस्ताव करता है तथा सरकार के 2023 के नारी शक्ति वंदन विधेयक के विपरीत इसमें महिला आरक्षण पर 15 साल की सीमा का प्रावधान भी नहीं है। विपक्षी दलों, खासकर डीएमके का तर्क है कि परिसीमन राजनीतिक मानचित्र को बदल देगा और इससे दक्षिणी राज्य नुकसान में रहेंगे।

विपक्ष के नेताओं ने जोर दिया कि वे महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं थे, बल्कि सरकार की जल्दबाजी में परिसीमन के सवाल को जोड़कर पुराने 2011 के जनगणना डेटा के आधार पर बिल पास कराने की चाल के खिलाफ थे, बिना सीटों के क्षेत्रीय वितरण,

जातियों और उपजातियों के बड़े सवाल को हल किए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कल कहा कि यदि सरकार इसे बिना परिसीमन लिंक के वापस लाती है, तो विपक्ष 2023 के मूल महिला आरक्षण बिल का 100 प्रतिशत समर्थन करेगा। ड्रमुक सांसद द्वारा पेश किया गया यह बिल विपक्षी पार्टियों की इस सूक्ष्म स्थिति को सामने लाने वाला पहला विधायी कदम है। ड्रमुक का बिल संविधान में संशोधन का प्रस्ताव करता है ताकि 2023 का महिला आरक्षण (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## ‘कैसे कराई जा रही है निर्धारित क्षेत्र के बाहर हाथी की सवारी’

जयपुर, 18 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने आमिर इलाके में अवैध रूप से हाथी सवारी के मामले में प्रमुख पुरातत्व सचिव, निदेशक, पर्यटन निदेशक, उप निदेशक पर्यटन और उप वन अधिकारी सहित, निजी पक्षकारों

## हाई कोर्ट ने पुरातत्व, पर्यटन तथा वन विभाग से जवाब मांगा।

को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश हाथी गांव विकास समिति की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि हाथी गांव में वन मंत्रालय के निर्देश पर आश्रय स्थल बनाए गए हैं। आरंभ में यहाँ करीब सौ हाथी रखे गए थे। वहीं बाद में समय के साथ महावतों की संख्या बढ़ने से (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## बी-टू-बाईपास पर बसी श्रीराम कॉलोनी और 2200 करोड़ रु. की 42 बीघा जमीन का विवाद पुनः गर्माया

हाऊसिंग बोर्ड के पक्ष में हाईकोर्ट की एकलपीठ के फैसले के विरोध में श्रीराम कॉलोनी बी-विकास समिति ने खंडपीठ में अपील दायर की

—कार्यालय संवाददाता—  
जयपुर, 18 अप्रैल। राजधानी जयपुर में बी-टू- बाईपास से द्रव्यवती नदी तक 2200 करोड़ रुपए की बेशकीमती 42 बीघा जमीन का विवाद सुनवाई अब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस.पी.शर्मा तथा जस्टिस सोमवार को होगी। शनिवार को हुई सुनवाई में हाऊसिंग बोर्ड ने भी अदालत को आश्चर्य किया है कि, खंडपीठ के समक्ष सोमवार को सुनवाई होने तक उनकी ओर से पत्राचार लेने की कार्रवाई नहीं की जाएगी। ज्ञात रहे कि बी-2-बाईपास रोड पर बसी श्रीराम कॉलोनी को जेडीए द्वारा

29 मई 1995 को दी गई योजना स्वीकृति और उसके बाद के आदेशों को अवैध मानते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ में जस्टिस गणेशराम मीणा ने गत 10 अप्रैल को राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड के पक्ष में फैसला सुनाया था। उन्होंने 31 जुलाई 1981 का समझौता विवरण भी अवैध मानते हुए शून्य घोषित कर दिया था। इस आदेश के बाद गत 16 अप्रैल को राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड ने करीब 2200 करोड़ रुपए की इस बेशकीमती जमीन का कब्जा लेने के लिए तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की थी। शुक्रवार को इस प्रकरण में श्रीराम कॉलोनी-बी विकास समिति की ओर से दायर अपील पर न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और अशोक कुमार जैन की

हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस.पी.शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ में सोमवार को इस प्रकरण में सुनवाई होगी। आवासन मंडल ने भी आश्चर्य किया है कि, सोमवार को खंडपीठ में सुनवाई होने तक उनकी ओर से पत्राचार लेने की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में जस्टिस गणेशराम मीणा की एकलपीठ ने गत 10 अप्रैल को हाऊसिंग बोर्ड के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जेडीए की ओर से 29 मई, 1995 को दी गई योजना स्वीकृति और उसके बाद के आदेशों को अवैध माना था। अदालत ने टिप्पणी की थी कि थोखाधड़ी से प्राप्त कोई भी आदेश अंतिम हो तो भी वह अवैध ही होता है।

खंडपीठ ने सुनवाई की। श्रीराम कॉलोनी विकास समिति की ओर से अधिवक्ता आशीष शर्मा ने राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ के फैसले तथा इसके बाद राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड द्वारा की जा रही तोड़फोड़ की कार्रवाई का विरोध जताया। अब इस प्रकरण की सुनवाई अब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस.पी.शर्मा तथा जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ में सोमवार को होगी। दूसरी ओर राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड की ओर से भी अदालत को आश्चर्य किया गया है कि जब तक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस.पी.शर्मा और शुभा मेहता की खंडपीठ के समक्ष सोमवार को इस मामले की सुनवाई नहीं हो जाती, तब

तक मौके पर पत्राचार लेने की कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी। गौरतलब है कि, राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड की ओर से दायर याचिकाओं पर राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस गणेशराम मीणा की एकलपीठ ने 10 अप्रैल को सुनवाई की थी। अदालत ने विवादित करीब 42 बीघा जमीन से जुड़े मामले में जेडीए की ओर से 29 मई, 1995 को दी गई योजना स्वीकृति और उसके बाद के आदेशों को अवैध माना है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि, थोखाधड़ी से प्राप्त कोई भी आदेश अंतिम हो तो भी वह अवैध ही होता है। अदालत ने माना कि 12 फरवरी, 2002 को एकलपीठ से गलत (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का डीए 2 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली, 18 अप्रैल। केन्द्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (डीआर) में 02 प्रतिशत की बढ़ोतरी को शनिवार को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस

## केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने इस बढ़ोतरी को मंजूरी दी।

आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में आयोजित पत्रकार वार्ता में मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने महंगाई के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए डीए और डीआर की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी है। इसमें मूल वेतन और पेंशन की मौजूदा दर 58 (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

# लालसोट में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दो चचेरे भाइयों को कुचला, मौत

हादसे के बाद आरोपी चालक कार मोंके पर छोड़कर फरार हो गया

लालसोट, (निसं)। दौसा जिले के लालसोट में शनिवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। कोथून रोड स्थित लाडपुरा मोड़ पर तेज रफ्तार बेकाबू कार ने बाइक सवार दो चचेरे भाइयों को पीछे से ऐसी टक्कर मारी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और दोनों युवक सड़क पर ही तड़पते हुए दम तोड़ बैठे। हादसे के बाद आरोपी चालक कार मोंके पर छोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में गुस्सा और दहशत का माहौल है।

पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान विराट मीणा (20) पुत्र शंकरलाल, श्रीराम मीणा (25) पुत्र रोशनलाल मीणा दोनों टोंक जिले के दत्तवास थाना क्षेत्र के जगसरा गांव निवासी और आपस में चचेरे भाई थे। दोनों के पिता सगे भाई



लालसोट में हुये हादसे के घायलों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया।

है। श्रीराम मीणा के बड़े भाई की शादी 20 अप्रैल को होनी थी। घर में तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन हादसे की खबर मिलते ही पूरे परिवार में

कोहराम मच गया। शादी के ठीक 2 दिन पहले घर से एक साथ दो जवान बेटों की अर्थियां उठने की नौबत आ गई। श्रीराम मीणा अपने पीछे 2 साल

का मासूम बेटा छोड़ गया, जो अब पिता के साथे से हमेशा के लिए वंचित हो गया। परिजनों ने बताया कि 16 अप्रैल को लगन समारोह में बांटने के

■ **मृतक श्रीराम मीणा के बड़े भाई की शादी 20 अप्रैल को होनी थी, घर में तैयारियां जोरों पर थी, हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया**

लिए स्टील के बर्तन लाए गए थे। शनिवार को दोनों युवक बचे हुए बर्तनों को दुकानदार को लौटाने के लिए लालसोट आ रहे थे।

सूचना मिलते ही लालसोट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शव मोर्चरी र्यूरी में रखवाए गए। दोनों क्षतिग्रस्त वाहन जब्त कर फरार कार चालक की तलाश जारी है।

## चौमूं में तेज रफ्तार पिकअप और स्लीपर बस में भीषण टक्कर



हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए पिकअप में फंसे चालक को बाहर निकाला।

चौमूं/जयपुर। चौमूं थाना क्षेत्र में जयपुर-सीकर हाईवे स्थित राधा स्वामी बाग चौराहे पर शनिवार सुबह एक तेज रफ्तार पिकअप और स्लीपर बस के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसा इतना जोरदार था कि सब्जियों से लदी पिकअप के परखच्चे उड़ गए और चालक वाहन में ही बुरी तरह फंस गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चौराहे पर स्लीपर बस खड़ी थी और यात्री उतर रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही पिकअप अनियंत्रित होकर बस में जा चुसी। टक्कर की आवाज से आसपास के लोग सहम उठे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते

■ **हादसे में सब्जियों से लदी पिकअप के परखच्चे उड़ गए और चालक वाहन में ही फंस गया**

■ **पिकअप में फंसे चालक को बाहर निकाल गंभीर हालत में नजदीकी निजी अस्पताल पहुंचाया**

हुए पिकअप में फंसे चालक को बाहर निकालने के लिए कड़ी मशक्कत की और उसे गंभीर हालत में नजदीकी निजी

अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों के अनुसार घायल की स्थिति नाजुक बनी हुई है और उपचार जारी है।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त वाहन को हटाकर यातायात बहाल कराया। हादसे के कारण नेशनल हाईवे-52 पर लंबा जाम लग गया, जिससे कई किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लग गईं और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। थाना प्रभारी हरबेन्द्र सिंह ने बताया कि चालक चालक की पहचान सतीश पुत्र सागरमल निवासी सीकर के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।

## 193 खेजड़ी काटने के मामले में तीन महीने बाद भी आरोपी गिरफ्तारी से दूर

बीकानेर, (निसं)। सरकार ने खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा तो दिया, लेकिन उसकी रक्षा को लेकर शुरू से ही उदासीनता बरती गई है। पूराल में सोलर प्लांट पर जनवरी में 193 खेजड़ी के पेड़ काटे गए थे। पटवारी ने प्लांट के सुरक्षा गार्ड और कर्मचारियों के खिलाफ राजकार्य में बाधा का केस दर्ज करवा दिया। हैरानी की बात है कि तीन महीने बाद भी इस केस में पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई, जबकि खेजड़ी कटाई के मामलों में एसपी के तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश हैं।

यह घटना 16 जनवरी 2026 की

■ **खेजड़ी कटाई के मामलों में एसपी ने तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दे रखे हैं**

है। पूराल में मैसर्स एनएचपीसी लिमिटेड के सोलर प्लांट पर खेजड़ी के 193 पेड़ काटे गए थे। पटवारी हंसराज और नायब तहसीलदार सुभाष मीणा मौके पर गए, लेकिन उन्हें प्लांट के बाहर ही रोक दिया गया। दोनों अधिकारी करीब एक घंटे तक बाहर ही खड़े रहे। इस संबंध में पटवारी

ने सुरक्षा गार्ड और कर्मचारियों के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मुकदमा धारा 132 बीएनएस के तहत पूराल थाने में दर्ज कराया था। मुकदमे की जांच एसएचओ समरवीर सिंह खुद कर रहे हैं, लेकिन अब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। एसएचओ का कहना है कि जांच चल रही है। यही नहीं, हाल ही में भानीपुरा में एक सोलर प्लांट पर राज्य वृक्ष खेजड़ी के 74 पेड़ काटने के मामले में कानूनी कार्यवाही के लिए तहसीलदार ने एसएचओ को परिवार दिया। उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सका है।

सोलर प्लांट लगाने के लिए राज्य

वृक्ष खेजड़ी की कटाई बंदस्तूर जारी है। एक अनुमान के अनुसार बीकानेर पांच साल में 60 हजार से ज्यादा खेजड़ी के पेड़ काटे जा चुके हैं। विशेष समाज और ग्रामीणों के विरोध के दबाव में ही हर बार उपखंड प्रशासन और पुलिस को कार्यवाही करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लगभग सभी मामलों में टेनेसी एक्ट की धारा 86 के तहत जुर्माना लगाकर सोलर कंपनियों को छोड़ा जा रहा था, लेकिन भली बुरा पूराल एसएडीएम ने पटवारी की सोलर कंपनी पर धारा 212 के तहत पेड़ों की कटाई पर ही रोक लगा दी है।

## चेक अनादरण के आरोपी को सजा सुनाई

अजमेर/मसूदा, (कासं)। चेक अनादरण के एक महत्वपूर्ण मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट, मसूदा ने अभियुक्त गणपत सिंह पुत्र गम सिंह निवासी मानपुरा को एक वर्ष के कारावास तथा एक लाख सत्तर हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने के आदेश जारी किए हैं। प्रकरण के अनुसार परिवारी सुखदेव सिंह रावत ने अपने अधिवक्ता पवन कुमार जीनगर के माध्यम से न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।

## पाँक्सो के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

मसूदा, (निसं)। ब्यावर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने पाँक्सो एक्ट के एक गंभीर मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास धुगतना होगा।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद हारून ने अपने फैसले में आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत 4 वर्ष, धारा 376 के तहत 10 वर्ष तथा पाँक्सो अधिनियम

■ **लगभग 33 माह तक चले इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 15 गवाह और 31 दस्तावेज पेश किए**

की धारा 3/4 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया। सभी धाराओं में अलग-अलग अर्थदंड भी निर्धारित किया गया है। अपर लोक अभियोजक ईश्वरचंद्र सौलंकी के अनुसार, मामला जुलाई 2023 का है। मसूदा थाना क्षेत्र

में एक नाबालिग पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि आरोपी ओमप्रकाश पुत्र मोहनलाल, निवासी मसूदा, ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगल ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। लगभग 33 माह तक चले इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 15 गवाह और 31 दस्तावेज प्रस्तुत किए। सभी साक्ष्यों और तथ्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई, जिससे पीड़िता को न्याय मिला।

## दीप्ति वर्मा का राजस्थान प्रशासनिक सेवा में भी चयन हुआ

दीप्ति वर्मा ने हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में 876वीं रैंक के साथ अपना स्थान बनाया था

जयपुर। विराटनगर के तेवड़ी गांव की बेटी दीप्ति वर्मा का हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन के बाद अब राजस्थान प्रशासनिक सेवा में भी चयन हुआ है।

■ **आरएसएस-2024 के परिणाम में भी दीप्ति वर्मा ने एससी महिला कैटेगरी में 27वीं रैंक के साथ जगह बनाई**

जानकारी के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में दीप्ति वर्मा ने हाल ही में 876वीं रैंक के साथ अपना स्थान बनाया था। वहीं शनिवार को



दीप्ति वर्मा

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी आरएसएस-2024 के परिणाम में भी दीप्ति वर्मा ने एससी महिला कैटेगरी में 27वीं रैंक के साथ जगह बनाकर परिवार

और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। दीप्ति वर्मा कोटपुतली बहरोड़ जिले के तहसील विराटनगर में गांव तेवड़ी की रहने वाली है। वर्तमान में दीप्ति अपने परिवार के साथ न्यू लोहा मंडी रोड, 14 नम्बर जयपुर में रहती हैं। दीप्ति के पिता दीलतराम बुनकर प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हैं और माता गृहणी हैं। दीप्ति वर्मा ने अपनी उच्च शिक्षा का श्रेय संत रामपालजी महाराज के आशीर्वाद, माता-पिता के सहयोग और निरंतर प्रयासों को दिया है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से शुरू हुई, 10वीं कक्षा विराटनगर से, 12वीं कक्षा जयपुर के हरमाड़ा स्थित मेहता स्कूल से और ग्रेजुएशन जयपुर के महारानी कॉलेज से उत्तीर्ण हुई है।

■ **पश्चिमी विक्षोभ से मौसम में बदलाव हुआ**

दिया, हालांकि शाम चार बजे के बाद आसमान में हल्के बादल छाये। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग ठंडा पेय पदार्थ पी रहे हैं। गर्मी से बचाव के लिए छाते और तौलिये का सहारा लिया जा रहा है।

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान में राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में बाड़मेर में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

शर्मा ने बताया कि राज्य के उत्तरी भागों में आज आंधी और बारिश के असर से तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इसके बाद आगामी दिनों में तापमान में पुनः 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। बढ़ती गर्मी के कारण अस्पतालों में उल्टी-दस्त के मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है।

## चूरू में गर्मी के तेवर शुरू, 42.4 डिग्री पहुंचा पारा

चूरू, (निसं)। पश्चिमी विक्षोभ के कारण अप्रैल में ही गर्मी ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। शनिवार को दोपहर करीब 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह 7 बजे से ही सूर्य की किरणें तेज हो गईं। दिन चढ़ने के साथ-साथ गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान कर

■ **पश्चिमी विक्षोभ से मौसम में बदलाव हुआ**

दिया, हालांकि शाम चार बजे के बाद आसमान में हल्के बादल छाये। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग ठंडा पेय पदार्थ पी रहे हैं। गर्मी से बचाव के लिए छाते और तौलिये का सहारा लिया जा रहा है।

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान में राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में बाड़मेर में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

शर्मा ने बताया कि राज्य के उत्तरी भागों में आज आंधी और बारिश के असर से तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इसके बाद आगामी दिनों में तापमान में पुनः 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। बढ़ती गर्मी के कारण अस्पतालों में उल्टी-दस्त के मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है।

## आरएसएस परीक्षा का परिणाम जारी, बाड़मेर के दिनेश विश्वाणंद प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहे

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने शनिवार को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2024 के साक्षात्कार का परिणाम जारी कर दिया। इस परिणाम में कुल 2391 अभ्यर्थियों को वरीयता सूची में स्थान दिया गया है।

परीक्षा में बाड़मेर के दिनेश विश्वाणंद ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं, जैसलमेर के वीरेंद्र चारण दूसरे तथा भीलवाड़ा के नवनीत शर्मा तीसरे

■ **जैसलमेर के वीरेंद्र चारण दूसरे तथा भीलवाड़ा के नवनीत शर्मा तीसरे स्थान पर रहे**

स्थान पर रहे हैं। आयोग द्वारा राज्य सेवाओं के 428 तथा अधीनस्थ सेवाओं के 668 पदों सहित कुल 1096 पदों के लिए 2461

अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 1 दिसंबर 2025 से 17 अप्रैल 2026 तक चरणबद्ध रूप से आयोजित किए गए थे।

आयोग सचिव के अनुसार, इस परीक्षा के तहत प्रारंभिक परीक्षा 2 फरवरी 2025 को आयोजित हुई थी, जिसमें पंजीकृत 6 लाख 75 हजार 80 अभ्यर्थियों में से 3 लाख 75 हजार 665 अभ्यर्थी शामिल हुए। 20 फरवरी 2025 को जारी प्रारंभिक

परीक्षा परिणाम के आधार पर 21 हजार 541 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। मुख्य परीक्षा 17 एवं 18 जून 2025 को आयोजित की गई, जिसमें 17964 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। मुख्य परीक्षा का परिणाम 20 अक्टूबर 2025 को घोषित किया गया था। परिणाम से संबंधित विस्तृत जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

■ **ट्रैक्टर लेकर आग बुझाने में जुटे किसान, बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया**

जानकारी के अनुसार, किसान अनिल काजला के करीब 35 बीघा खेत में गेहूं की फसल कटाई के लिए तैयार खड़ी थी। अचानक ऊपर से गुजर रही जर्जर 11 केवी लाइन का तार टूटकर गिरा और फसल में आग लग गई। इस हादसे में करीब 10 बीघा फसल पूरी तरह जलकर खाक हो गई, जिससे

जानकारी के अनुसार, किसान अनिल काजला के करीब 35 बीघा खेत में गेहूं की फसल कटाई के लिए तैयार खड़ी थी। अचानक ऊपर से गुजर रही जर्जर 11 केवी लाइन का तार टूटकर गिरा और फसल में आग लग गई। इस हादसे में करीब 10 बीघा फसल पूरी तरह जलकर खाक हो गई, जिससे

## नाकाबंदी में कार से 46 लाख रुपये बरामद, दो गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। कनवास पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान कारवाई करते हुए एक कार से करीब 46 लाख रुपये बरामद कर दो जनों को गिरफ्तार किया। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिये ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकल्याण मीणा के निर्देशन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

ग्रामीण एसपी ने बताया कि पुलिस उप अधीक्षक वृत्त सांगोद नरेंद्र जैन के सुपरविजन व अंकित कुडी आरपीएस (प्रो.) कनवास थाने के थानाधिकारी अनूप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्ययोजना बनाकर कनवास तिराहा मोरुकला एनएच-52 पर नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान एक कार झालावाड़ की तरफ से आती हुई दिखी जिसे रुकवाया तो कार चालक द्वारा धागे का प्रयास किया। पुलिस टीम में चालक व कार में बैठे व्यक्ति को मौके

पर डिटेन कर कार की तलाशी ली तो कार में 46,77,860 रुपये नकद बरामद किये गये। ग्रामीण एसपी ने बताया कि पुलिस टीम ने कार में बैठे दोनों से नकदी के बारे में पुछताछ की तो कोई संतोषपद जवाब नहीं दिया गया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि पुलिस टीम ने कारवाई करते हुए कार से बरामद की गई नकदी को जब्त किया एवं शांतिभंग में जिला आगरा उत्तरप्रदेश के चन्द्रसोरा निवासी शैलेन्द्र शर्मा (27) एवं जिला झांसी के चौकी निवासी अभयराज सिंह (21) को गिरफ्तार किया। बरामद की गई राशि के बारे में आयकर व जीएसटी विभाग को भी जानकारी दी गई, मामले में जांच की जा रही है।

■ **कोटा ग्रामीण की कनवास पुलिस टीम ने की कारवाई**

■ **कोटा ग्रामीण की कनवास पुलिस टीम ने की कारवाई**

■ **कोटा ग्रामीण की कनवास पुलिस टीम ने की कारवाई**

पर डिटेन कर कार की तलाशी ली तो कार में 46,77,860 रुपये नकद बरामद किये गये। ग्रामीण एसपी ने बताया कि पुलिस टीम ने कार में बैठे दोनों से नकदी के बारे में पुछताछ की तो कोई संतोषपद जवाब नहीं दिया गया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि पुलिस टीम ने कारवाई करते हुए कार से बरामद की गई नकदी को जब्त किया एवं शांतिभंग में जिला आगरा उत्तरप्रदेश के चन्द्रसोरा निवासी शैलेन्द्र शर्मा (27) एवं जिला झांसी के चौकी निवासी अभयराज सिंह (21) को गिरफ्तार किया। बरामद की गई राशि के बारे में आयकर व जीएसटी विभाग को भी जानकारी दी गई, मामले में जांच की जा रही है।

## सीकर में दो महिलायें लापता

सीकर, (निसं)। जिले में एक महिला और युवती के लापता होने का मामला सामने आया है। युवती मजदूरी करने के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। वहीं महिला अपनी चार साल की बेटी को लेकर कहीं चली गई। वह भी वापस घर नहीं लौटी है। 28 साल की युवती के भाई ने पुलिस में शिकायत देकर बताया कि उनकी पत्नी अपनी चार साल की बेटी को लेकर 17 अप्रैल को दोपहर को बाड़मेर चली गई। काफी देर बाद तक जब वापस नहीं लौटी तो दोनों की तलाश की गई। दोनों ही मामलों में पुलिस जांच कर रही है।

## काटली नदी और सहायक जल स्रोतों को बचाने के लिए जन आंदोलन तेज

एनजीटी आदेश की पालना के लिए लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा

उदयपुरवाटी, (निसं)। काटली नदी और उसके सहायक जल स्रोतों को बचाने के लिए अब जनआंदोलन तेज हो गया है। काटली नदी बचाओ जन अभियान के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने उपखण्ड अधिकारी और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर नदी, नालों और जल स्रोतों के सीमांकन, अतिक्रमण हटाने और संरक्षण की मांग उठाई है। यह कार्रवाई राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के 7 अप्रैल के आदेश के अनुपालन को लेकर की

गई, जिसमें जल स्रोतों की सुरक्षा को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। अभियान संयोजक सुभाष करण के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में साफ कहा गया कि उदयपुरवाटी क्षेत्र में काटली नदी के सहायक जल स्रोत सुकली नदी, जहाज मावता, मोजिडा नाला, सांका वाला नाला, जोधपुरनाला, सोकली नदी सराय, सटिण्डा नाला सहित कई स्रोत-अतिक्रमण और उपेक्षा के कारण संकट में हैं। ज्ञापन में मांग की गई कि इन सभी जल स्रोतों का तत्काल सीमांकन कर

■ **उपखण्ड अधिकारी और तहसीलदार को सौंपे ज्ञापन में नदी, नालों और जल स्रोतों के सीमांकन, अतिक्रमण हटाने और संरक्षण की मांग उठाई**

अतिक्रमण हटाया जाए और प्राकृतिक जल निकासी मार्गों को दुरुस्त किया जाए, ताकि क्षेत्र में जल संकट को रोकना जा सके। ज्ञापन में प्रशासन से आग्रह किया गया कि सभी पटवारीयों को निर्देशित कर जल स्रोतों की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट तैयार करवाई जाए। अवैध कब्जों

की पहचान कर तुरंत कार्रवाई की जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में बुद्धिजीवियों, अधिवक्ताओं और ग्रामीणों ने हस्ताक्षर कर इस मांग को जनसमर्थन दिया। ज्ञापन में मांग की गई कि सिंधु नदी का जल काटली में लाया जाए और नदी के समग्र विकास, संरक्षण और

प्रभावितों के पुनर्वास की योजना बनाई जाए। अभियान संयोजक सुभाष करण ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा और जल्द ही प्रधानमंत्री से मुलाकात कर मांग रखी जाएगी। ज्ञापन के दौरान सतीश मिश्रा, धर्मवीर यादव, दीपक मीणा, करण हेतलवाल, धनसिंह करण, मोहर सिंह, तरलाल सेनी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिन्होंने काटली नदी बचाने के इस अभियान को जनआंदोलन का रूप देने का संकल्प लिया।

# 17 देशों के 43 प्रतिभागियों ने देखी राजस्थान विधानसभा, विधायी मसौदे पर भी चर्चा

## स्पष्ट और सरल भाषा में जनता की इच्छाएं प्रतिबिंबित करने वाला हो विधायी मसौदा : वासुदेव देवनानी

**-कार्यालय संवाददाता-**  
जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि कानून निर्माण में विधायी मसौदा महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि विधायी मसौदे में स्पष्ट व सरल भाषा में जनता की इच्छाएं प्रतिबिंबित होनी चाहिए। स्पिकर देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधान सभा में विधेयक को पारित कराने की प्रक्रिया अत्यंत सावधानी पूर्वक और पारदर्शी तरीके से की जाती है। कानून में सर्वोत्तम गुणवत्ता के सभी पहलुओं का समावेश सुनिश्चित किया जाता है। स्पिकर देवनानी शनिवार को यहां राजस्थान विधान सभा में इन्टरनेशनल लेजिस्लेटिव ड्रॉइंग विषय पर विधायी मसौदा तैयार करने के लिए 37 वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। देवनानी ने बांग्लादेश, भूटान, घाना, केन्या, श्रीलंका, तंजानिया, जाम्बिया सहित 17 देशों के 43 प्रतिभागियों से परिचय किया और उनके साथ सामूहिक चित्र भी कराया। यह कार्यक्रम भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग योजना के अंतर्गत लोकसभा सचिवालय के पार्लियामेन्ट्री रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसिस द्वारा आयोजित हुआ।



स्पिकर वासुदेव देवनानी शनिवार को राजस्थान विधानसभा में 17 देशों के 43 प्रतिभागियों से रूबरू हुए। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग भी मौजूद थे।

प्रक्रिया तीन मुख्य चरणों से गुजरती है। उन्होंने कहा कि विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है। द्वितीय चरण में विधेयक पर गहन चर्चा के साथ मसौदे को बेहतर बनाने के लिए अक्सर विशेष समितियों की मदद से हर पहलु का बारीकी से विश्लेषण कराये जाने के पश्चात सदन मतदान के लिए एकत्रित होता है। कानून को सशक्त, समझने में आसान और वास्तव में जनता के हित में बनाने के लिए सम्पूर्ण प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक सुनिश्चित किया जाता है। स्पष्ट और सरल भाषा का प्रयोग ही न्याय का सार होता है। देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधान सभा लोकतंत्र का सच्चा मंदिर है। यहां सभी का एक साथ विकास करने और महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कानून पारित कराये जाते हैं।

विधान सभा अपने गौरवशाली स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रही है। राज्य के निर्माण के शुरुआती दिनों से लेकर आज के डिजिटल शासन के युग तक विधान सभा में लाखों लोगों के सपनों को कानून में तब्दील किये जाते हैं। 200 सदस्यों वाली राजस्थान विधानसभा का महत्वपूर्ण हिस्सा आधुनिक डिजिटल संग्रहालय है। यह संग्रहालय जनता विशेषकर युवाओं से जुड़ने का एक सेतु है। देवनानी ने विदेशी प्रतिभागियों से कहा कि राजस्थान विधान सभा के वरिष्ठ और अनुभवी विधायकों के साथ चर्चा विधायी ज्ञान को बढ़ाएगी। ऐसे कार्यक्रम किताबों से परे जाकर अनुभव जानने के दुर्लभ अवसर हैं और संसदीय प्रक्रिया का वास्तविक ज्ञान भी होते हैं। कानून बनाना शासन

को वैश्विक भाषा है, जिसे साझा करके हम सभी दुनियाभर में लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सहभागी बनेंगे। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान, विधायक डॉ. गोपाल शर्मा, चन्द्रभान सिंह आक्या, कैलाश वर्मा, गुरवीर सिंह, डॉ. शिखा मील बराला मौजूद थे। राजस्थान विधान सभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा, लोकसभा के प्राइड कार्यक्रम के निदेशक राजकुमार और कार्यक्रम निदेशक एम. चतुर्वेदी ने 37वें प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी। भूटान की नेशनल एसेम्बली सचिवालय की विधायी अधिकारी फूपां डेमा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। तंजानिया,

**गुलाबी शहर के गुलाबी सदन में विधानसभाध्यक्ष ने विदेशी प्रतिभागियों को बताई जनहित में विधायिका की भूमिका**

केन्या और मलेशिया के प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के दौरान केंद्र और राज्य के विषय, महिला आरक्षण, वल-बदल विरोध अधिनियम तथा प्राइवेट बिलों से संबंधित प्रश्न किए। प्रश्नों के उत्तर में सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग एवं प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान ने विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान करते हुए विधायी प्रक्रिया के व्यावहारिक पहलुओं को स्पष्ट किया। विदेशी प्रतिभागियों और विधायकों के मध्य सार्थक संवाद हुआ। लगभग एक घंटे चले संवाद में लोकतंत्र के विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। विदेशी प्रतिभागियों ने राजस्थान विधान सभा के राजनैतिक आख्यान संग्रहालय को सराहना की। उन्होंने संग्रहालय को ज्ञानवर्धक एवं आकर्षक बताते हुए कहा कि इस प्रकार के संग्रहालय लोकतांत्रिक परंपराओं को समझने का प्रभावी माध्यम है। प्रतिभागियों ने ऐसे संग्रहालय की सभी देशों में आवश्यकता जताई।

**इस अंश पूंजी सहयोग के बदले राजस्थान वित्त निगम द्वारा रीको को समान मूल्य के इक्विटी शेयर आवंटित किए जाएंगे।**

रीको के निदेशक मंडल की स्वीकृति के बाद दोनों संस्थाओं के बीच शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट भी किया जा चुका है। इसके तहत चरणबद्ध तरीके से राशि जारी की जा रही है। प्रथम किश्त के रूप में 10 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके थे, जबकि दूसरी किश्त के रूप में भी 10

## राज्य वित्त निगम को रीको प्रशासन देगा 50 करोड़ रु. अंश पूंजी का सहयोग

### औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इस रकम में से 20 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं

**-कार्यालय संवाददाता-**  
जयपुर। राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) द्वारा राजस्थान वित्त निगम को 50 करोड़ रुपये का अंश पूंजी सहयोग देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत अब तक 20 करोड़ रुपये की राशि जारी भी कर दी गई है, जिससे निगम की वित्तीय स्थिति को मजबूती मिलने लगी है।

जानकारी के अनुसार, यह निर्णय राज्य सरकार की वित्तीय वर्ष 2024-25 की संशोधित बजट घोषणा के अनुरूप लिया गया है, जिसमें राजस्थान वित्त निगम के सुदृढीकरण के लिए सरकार और रीको द्वारा 50-50 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया गया था।

## निवेशकों से ठगी करने वाले आरोपी को जमानत नहीं

### महंगी गाड़ियों और हाई रिटर्न का झांसा देकर करोड़ों रुपए ऐंठने का मामला

**जयपुर (कासं)।** राजस्थान हाईकोर्ट ने निवेशकों को महंगी गाड़ियों और हाई रिटर्न का लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने के आरोप में जेल में बंद आरोपी बंशीलाल को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है। जस्टिस प्रवीर भटनगर की एकलपीठ ने यह आदेश बंशीलाल की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

जमानत याचिका में कहा गया कि उसने डिजिटल करंसी बनाने और लिस्टेड कराने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की थी। इसके अलावा उसने किसी प्रकार की ठगी नहीं की। रजिस्ट्रेशन कर व्यापार करना अपराध नहीं है। इस व्यापार से उसे करीब 2.20 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, जिसे उसने खुदबुद नहीं किए हैं। इसके अलावा वह सात माह से जेल में बंद है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए जिसका विरोध करते हुए सरकारी

वकील विजय सिंह यादव ने कहा कि आरोपी ने ग्रामिक विज्ञान कर हर निवेशक को महंगी कार देने का आश्वासन दिया और करीब 250 लोगों से 15 करोड़ रुपए प्राप्त किए वहीं भारत सरकार को सूचित किए बिना डिजिटल करंसी बनाई और ऑनलाइन करीब पांच करोड़ रुपए प्राप्त किए। ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है।

## प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में राज्य सरकार ने 1150 करोड़ रु. जारी किए

### खरीफ 2025 में किसानों के 2237 करोड़ के दावों का त्वरित वितरण सुनिश्चित : कृषि मंत्री

**जयपुर।** कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल ने बताया कि राजस्थान सरकार ने किसानों के हित में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 सत्र के लिए एंजीकृत 2.17 करोड़ बीमाधारकों को 1150.04 करोड़ रुपये की राज्यांश अनुदान राशि का भुगतान कर दिया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा का मजबूत कवच मिलेगा। कृषि मंत्री ने बताया कि योग्य

फसल बीमा पॉलिसीधारक किसानों को खरीफ 2025 के तहत देय लगभग 2237 करोड़ रुपये के दावों का शीघ्र, त्वरित एवं प्राथमिकता आधार पर वितरण किया जाएगा। इससे प्रभावित किसान परिवारों को समय पर वित्तीय सहायता मिल सकेगी, जो उनकी आय सुरक्षा की दिशा में मील का पथर साबित होगी। यह योजना किसानों को असफल हुआई, हुआई से कटाई तक खड़ी फसलों में प्राकृतिक आपदाओं से क्षति तथा कटाई उपरान्त 14 दिनों की

अवधि में पोस्ट-हार्वेस्ट लॉस पर पूर्ण बीमा लाभ प्रदान करेगी। राज्य सरकार दावों के सत्यापन को पारदर्शी, त्वरित एवं तकनीकी आधारित बनाने के लिए कटिबद्ध है, ताकि कोई किसान विलंब का शिकार न हो। बताया जा रहा है कि किसानों द्वारा 466.14 करोड़ रुपये का प्रीमियम जमा करवाया गया है। किसानों को प्रीमियम कम पड़े इसके लिए राज्य सरकार द्वारा राज्यांश प्रीमियम अनुदान 1150.04 करोड़ रुपये और

केंद्र सरकार द्वारा राज्यांश प्रीमियम अनुदान 1150.04 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ कम पड़े। कृषि मंत्री ने कहा कि 'राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी करने और जोखिमों से सुरक्षा के प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध है। फसल बीमा योजना की ओर मजबूत बनाकर हर योग्य किसान तक लाभ पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।' यह कदम राजस्थान के किसानों के लिए वरदान सिद्ध होगा।

## मुख्यमंत्री ने अक्षय तृतीया की बधाई दी

### -कार्यालय संवाददाता-

**जयपुर।** मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अक्षय तृतीया (19 अप्रैल) पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। यह तिथि नए कार्यों की शुरुआत और मांगलिक आयोजनों के लिए अत्यंत शुभ और पुण्यफलदायी है। शर्मा ने कहा कि प्रगतिशील और जागरूक समाज के निर्माण के लिए प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे समाज में व्याप्त बाल-विवाह जैसी कुरीतियों को दूर करने में अपना योगदान दें।

## बाधिन 'भक्ति' ने दो शावकों को जन्म दिया

**जयपुर (कासं)।** नाहरगढ़ जैविक उद्यान में मादा बाधिन 'भक्ति' ने 18 अप्रैल को शुरुवार देर रात दो स्वस्थ शावकों को जन्म दिया। जन्म के बाद विशेष परिस्थितियों के चलते शावकों को चिकित्सकीय देखरेख में रखा गया है। उप वन संरक्षक (वनजीव) चिड़ियाघर जयपुर विजय पाल सिंह ने बताया कि जन्म के बाद लंबे समय तक बाधिन द्वारा शावकों को दूध नहीं मिलाने पर पशु चिकित्सकीय बोर्ड के निर्णय

**■ नाहरगढ़ जैविक उद्यान की टीम देखभाल में जुटी**  
के अनुसार दोनों शावकों को मां से अलग किया गया। इसके बाद उन्हें तुरंत उद्यान के पशु चिकित्सालय में संचालित नियोजित केयर यूनिट में शिफ्ट किया गया। शावकों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद पशु चिकित्सा दल द्वारा उनकी देखभाल शुरू की गई।

उपनिदेशक डॉ. अरविंद कुमार माथुर स्वयं शावकों को फीडिंग और स्वास्थ्य की सतत निगरानी कर रहे हैं। उद्यान प्रशासन ने शावकों की देखभाल के लिए तीन कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी लगाई है, जो आठ-आठ घंटे की पारी में उनकी निगरानी और देखरेख सुनिश्चित कर रहे हैं। फिलहाल दोनों शावक चिकित्सकों की निगरानी में हैं और उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

उपनिदेशक डॉ. अरविंद कुमार माथुर स्वयं शावकों को फीडिंग और स्वास्थ्य की सतत निगरानी कर रहे हैं। उद्यान प्रशासन ने शावकों की देखभाल के लिए तीन कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी लगाई है, जो आठ-आठ घंटे की पारी में उनकी निगरानी और देखरेख सुनिश्चित कर रहे हैं। फिलहाल दोनों शावक चिकित्सकों की निगरानी में हैं और उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

## मुहाना मंडी में निरीक्षण

**जयपुर।** खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने मुहाना फल मंडी में शनिवार को औचक निरीक्षण किया। सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मिश्रल के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। मिश्रल ने बताया कि फलों को हानिकारक रसायनों से पकाने की रोकथाम के लिए चल रहे विशेष अभियान के तहत मंडी में बड़े व्यापारियों के गोदामों का निरीक्षण किया गया।

## कृषि उपज मंडियों में 21 करोड़ के विकास कार्य होंगे

**जयपुर।** मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा कृषि उपज मंडी समितियों में सुविधा विस्तार एवं आधारभूत संरचना निर्माण के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मण्डियों में 21 करोड़ 26 लाख रुपये से अधिक के विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है। कृषि उपज मण्डी समिति, चौमहला (शालावाड), कुचामन सिटी, 'विशाल श्रेणी' बारा, कोटा (अनाज) एवं प्रतापगढ़ में मण्डी यार्ड के निर्माण कार्य एवं विद्युत संबंधी कार्य करवाए जाएंगे।

## गृह सचिव और पुलिस प्रशासन बताए पदोन्नति छोड़ने के चलते रिक्त पदों को क्यों नहीं भरा गया?

**जयपुर।** राजस्थान हाईकोर्ट ने गृह सचिव और पुलिस प्रशासन को नोटिस जारी कर पूछा है कि कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल पदोन्नति के दौरान पद छोड़ने से रिक्त रहे पदों को उसकी साल की प्रतीक्षा सूची से क्यों नहीं भरा जा रहा है। जस्टिस रविचिरानिया की एकलपीठ ने यह आदेश नरेन्द्र कुमार मीणा की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल की साल 2025-26 की पदोन्नति के दौरान 13 पुलिसकर्मियों ने पदोन्नति को अस्वीकार कर दिया। ऐसे में नियमानुसार खाली रहे पदों को इसी साल की प्रतीक्षा सूची से भरा जाना चाहिए। इस संबंध में 8 मई, 2020 को जारी स्टैंडिंग ऑर्डर में भी कहा गया है कि स्क्रॉनिंग प्रणाली से चयन के बाद रिक्त रहे पदों को उसी साल योग्यता परीक्षा के माध्यम से उसी साल की रिक्तियों में शामिल कर भरा जाएगा। इसके बावजूद भी इन पदों को आगामी साल के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए रिक्त पदों को अन्य अभ्यर्थियों से नहीं भरने को कहा है।

## राजस्व अर्जन और मिनरल ब्लॉक के वार्षिक रोडमैप की कवायद में जुटा खनन विभाग

### प्रदेश में बंद पड़ी खानों को पुनः चालू करके खनन कार्य शुरू करवाने के निर्देश

**-कार्यालय संवाददाता-**  
**जयपुर।** राज्य के माईस विभाग ने वर्ष 2026-27 के राजस्व लक्ष्य संग्रहण की कवायद शुरू की है। वित्तीय वर्ष के दौरान मेजर और माइनर मिनरल ब्लॉकों और प्लॉटों के तैयार करने से लेकर आंखान तक का कलेण्डर बनाने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव माईस एवं पेट्रोलियम अर्पणा अरोरा ने अधिकारियों को राजस्व वसूली के सभी संभावित स्रोतों पर फोकस करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश में वैध खनन को बढ़ावा और अवैध खनन पर कारगर रोक के लिए मिनरल क्षेत्रों में डेलिनेवेशन, प्लॉट या ब्लॉक तैयार करने और आंखान की टाइमलाइन बनाते हुए रोडमैप तैयार करने को कहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में बंद पड़ी खानों में उत्पादन आरंभ कराने की कवायद की जाए ताकि बंद खानों में खनन आरंभ होने से आर्थिक विकास, रोजगार और राजस्व के अवसर विकसित हो सके। एएफएस माईस अर्पणा अरोरा शनिवार को खनिज भवन में विशिष्ट सचिव नम्रता वृष्णा, निदेशक माईस महावीर प्रसाद मीणा और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रही थीं।



खनन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अर्पणा अरोरा ने शनिवार को अधिकारियों की बैठक की।

राजस्व संग्रहण के कारगर प्रयास और मिनरल ब्लॉकों की नीलामी पर जोर देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि माईस विभाग राज्य के राजस्व में प्रमुखता से योगदान देने वाला विभाग है। हाल ही में समाप्त हुए वित्त वर्ष में 13 प्रतिशत विकास दर के साथ 10394 करोड़ रु. का रिकॉर्ड राजस्व संग्रहित किया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए 39 फीसदी बढ़ोतरी के साथ 14001 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया है। उन्होंने इसे चुनौती के रूप में लेते हुए राजस्व वसूली के सभी संभावित स्रोतों पर अभी से फोकस करते हुए राजस्व

संग्रहण का कार्यालयवार मासिक रोडमैप बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व छोजत के सभी संभावित क्षेत्रों पर प्राथमिक रोक लगानी होगी। अर्पणा अरोरा ने वैध खनन को बढ़ावा देने के लिए मिनरल खोज, डेलिनेवेशन, मेजर और माइनर मिनरल ब्लॉक के आंखान के लिए प्लॉट और ब्लॉक तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने फ्री एम्बेडेड प्लॉट और ब्लॉक तैयार करने पर जोर देते हुए कहा कि इससे नीलाम किये जाने वाले मिनरल ब्लॉक व प्लॉट शीघ्र परिचालन में आ सकेंगे। अतिरिक्त निदेशक भूविज्ञान व

मुख्यकार्यकारी आरएसएमईटी आलोक प्रकाश जैन को इसके लिए प्रभारी अधिकारी बनाते हुए टाइम लाइन तय करते हुए मासिक रोडमैप बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि टाइमलाइन व रोडमैप बनाने से क्रियान्वयन में आसानी होने के साथ ही मोनेटरींग व्यवस्था चाक चोबंद हो सकेगी। विशिष्ट सचिव माईस नम्रता वृष्णा ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राजस्व संग्रहण के लिए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ही प्रयास जारी रखने होंगे। निदेशक माईस महावीर प्रसाद मीणा ने बताया कि हाल ही समाप्त हुए

अरविन्द सारस्वत, अतिरिक्त निदेशक वाईएस सहावल, विशेषाधिकारी श्रीकृष्ण शर्मा, एसजी सुनील वर्मा, अधीक्षण खनिज अभियंताओं में एनएस शक्तावत, डॉ. धर्मेन्द्र लोहार, प्रताप मीणा, जयगुरुबख्खानी, कमलेश्वर बोरोगामा, एसपी शर्मा, ओपी कावरा, देवेन्द्र गौड़, एनके बैरवा, सुनील शर्मा, अविनाश कुलदीप, सत्यनारायण कुमावत, एमई जयपुर श्याम कापड़्य, अधीक्षण भूविज्ञानी संजय सक्सीना, नितिन चौधरी, अतिरिक्त निदेशक आईटी शीतल अग्रवाल, एडीजी श्री गोपालाराम, एसजी नितिन चौधरी सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

**■ सरकार ने वर्ष 2026-27 में 14001 करोड़ रुपए के राजस्व अर्जन का लक्ष्य रखा जाएगा।**

## नारी शक्ति बिल पास नहीं होने पर भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन

**जयपुर।** भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा ने नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम के लोकसभा में पारित नहीं हो पाने के मुद्दे को लेकर शनिवार को राजधानी जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता सड़कों पर उतरीं और विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इसे महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ कदम बताया। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पहले पार्टी मुख्यालय पर एकत्र हुईं, जहां से चौमू सर्किल तक मार्च निकाला गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता तख्ताओं लेकर नारे लगाते हुए आगे बढ़ीं। उनका कहना था कि यह विधेयक देश की आधी आबादी को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से लाया गया था, लेकिन विपक्ष ने इसका विरोध कर महिलाओं के हितों के प्रति अपनी नकारात्मक सोच उजागर की है। भाजपा महिला मोर्चा को प्रदेश

**■ भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने कहा कि संसद में इस बिल के खिलाफ मतदान करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।**

सशक्तिकरण उनके लिए केवल एक नारा बनकर रह गया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुमन शर्मा ने विपक्ष के रवैये को अहंकार पूर्ण बताते हुए कहा कि सदन में बिल गिरने के बाद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आपत्तिजनक थी। उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं इस व्यवहार को नहीं भूलेंगी। साथ ही विपक्ष की महिला नेताओं प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव के रुख को भी निराशाजनक बताया। प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता गैना ने महिलाओं से एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का आ आ किया। उन्होंने कहा कि जब समाज की आधी आबादी संगठित होती है, तो कोई भी शक्ति उनके अधिकारों को दबा नहीं सकती। भाजपा नेताओं ने बताया कि 20 अप्रैल को जयपुर में प्रदेश भर से हजारों महिलाएं एकत्रित होकर इस मुद्दे पर बड़ा प्रदर्शन करेंगी। फिलहाल इस विरोध प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है।





# बंगाल में डबल इंजन सरकार से तीव्र विकास होगा- भजनलाल

## मुख्यमंत्री ने कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को संबोधित किया

कोलकाता/जयपुर, 18 अप्रैल। स्वाभिमान और देशभक्ति हर राजस्थानी के मन में समाहित है, यह बात राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पश्चिमी बंगाल में एक सभा को सम्बोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा, राजस्थानी देश-दुनिया में कहीं भी चले जाएं, सामाजिक संस्कारों से अपना स्थान बना ही लेते हैं। उन्होंने अपनी

मुख्यमंत्री भजनलाल ने पहले कालीघाट मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। फिर बेलीगंज स्थित गोविन्दम इस्कॉन मंदिर में राधा-कृष्ण के दर्शन किए व पूजा की।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को कोलकाता में आयोजित राजस्थान प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किया।

कर्मभूमि और जन्मभूमि दोनों से गहरा जुड़ाव बनाए रखा है। वे दुनिया के हर हिस्से में अपनी मेहनत, संघर्ष और सफलता से राजस्थान का गौरव बढ़ा रहे हैं। शर्मा इस समय प.बंगाल के चुनावी दौर पर हैं, जहां उन्होंने कोलकाता में प्रवासी राजस्थानियों की एक सभा में यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से प्रवासी राजस्थानियों के जुड़ाव को और मजबूत किया जा रहा है। वर्तमान में राजस्थान फाउंडेशन के 40 चैप्टर्स संचालित हैं।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम से पहले कालीघाट मंदिर और गोविंदम इस्कॉन

मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने कालीघाट मंदिर में विधि-विधान से मां काली की पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री कोलकाता के बेलीगंज स्थित गोविंदम इस्कॉन मंदिर पहुंचे और वहां श्री राधा कृष्ण के दर्शन और पूजा-अर्चना की। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ चाय पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होना सुनिश्चित है। हम सभी को मिलकर भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में विजयी बनाना है। पश्चिम बंगाल की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। अगर पश्चिम बंगाल में भी राजस्थान जैसा

विकास चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाने के लिए जुट जाएं। पश्चिम बंगाल में भी डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में तीव्र विकास होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में हर क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास, ऊर्जा, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र में राजस्थान तेजी से उभर रहा है और यह प्रवासी व स्थानीय उद्योगों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में कृषि, बिजली, पानी सहित, विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य किए जा रहे हैं। विभिन्न

परियोजनाओं के माध्यम से हर जिले में सुचारू आपूर्ति के लिए कार्य किया जा रहा है। राजींग राजस्थान इवेस्टमेंट समित के माध्यम से भी युवाओं के लिए रोजगार के भरपूर अवसर सृजित किए गए हैं।

इस दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष ड.राजेन्द्र राठौड़, संयोजक राजस्थान प्रवासी प्रकोष्ठ कुमार लखोटिया, अध्यक्ष राजस्थान फाउंडेशन पश्चिम बंगाल संतोष कुमार पुरोहित, राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव लघु उद्योग भारती नरेश पारीक सहित, बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी एवं भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

## डीएमके ने अपने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) तुरंत लागू हो, कुल सीटों की संख्या बढ़ाए बिना और किसी जनगणना या परिसीमन की प्रतीक्षा किए बिना। सरकार के 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विपरीत, जिसने आरक्षण को 15 वर्षों तक सीमित किया था, द्रमुक का बिल आरक्षण को स्थायी बनाने का प्रस्ताव करता है। द्रमुक ने शुक्रवार को राज्यसभा अध्यक्ष को नियम 267 के तहत नोटिस दिया, जिसमें उस दिन के सत्र को स्थगित कर महिला आरक्षण पर तुरंत चर्चा कराने का अनुरोध किया गया।

## सम्राट चौधरी 24 अप्रैल को विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे

पटना, 18 अप्रैल। बिहार विधानसभा का दूसरा सत्र आगामी 24 अप्रैल 2026 को बुलाया गया है। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह सत्र केवल एक दिन का होगा।

## एक दिन के सत्र के लिये अधिसूचना जारी।

और सुबह 11 बजे विधानसभा परिसर में आयोजित किया जाएगा। राजनीतिक दृष्टि से यह सत्र बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह सत्र सरकार को इसी दिन सदन में अपना बहुमत साबित करना होगा।

## लोकसभा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) किया, और राष्ट्रपति के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा 2 घंटे 46 मिनट चली।

## बी-टू-बाईपास पर बसी श्रीराम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) तथ्यों से आदेश प्राप्त किया गया था, ऐसे में उसे रद्द किया जाता है। अदालत ने साल 1986 की ऑडिट रिपोर्ट और 25 जुलाई, 2019 की जांच समिति रिपोर्ट के आधार पर माना कि अधिग्रहण से पूर्व ऐसी कोई योजना अस्तित्व में ही नहीं थी और समिति ने मूल खातेदारों की भी पश्चानुवृत्ति नहीं बनायी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि खातेदार सिविल कोर्ट में जमा मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं और आवासन मंडल भी विधि सम्मत कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। प्रकरण से जुड़े अधिवक्ता दिनेश यादव ने बताया कि साल 1981 में जबहरपुरी भवन निर्माण सहकारी समिति ने खातेदारों से समझौता विक्रय के आधार पर भूमि खरीदने का दावा

## सोमवार को हो सकती है अमेरिका -ईरान में अगले दौर की वार्ता

### पाकिस्तानी सूत्रों ने बताया इस्लामाबाद में हो रही वार्ता के कवरज के लिए दुनिया भर से मीडियाकर्मी आ रहे हैं।

इस्लामाबाद, 18 अप्रैल। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को खत्म करने के लिए अहम बातचीत का दूसरा दौर इस्लामाबाद में सोमवार को शुरू हो सकता है। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के आगमन की तैयारियां भी तेज हो गई हैं।

यह घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है, जब पाकिस्तान सक्रिय मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए शांति बहाली को कोशिश में जुटा है और हाल ही में सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने तेहरान में उच्चस्तरीय बैठकों के जरिए कूटनीतिक प्रयासों को नई दिशा दी है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह बातचीत लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को खत्म करने की दिशा में कोई ठोस परिणाम दे पाएगी। ट्रिपल की सरकारों संवाद समिति अनादोलू एजेंसी ने पाकिस्तानी सूत्रों के हवाले से बताया कि अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडलों के आने के

## अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा है कि अगर वार्ता सफल रहे तो वे भी पाकिस्तान आएंगे।

लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि युद्ध खत्म करने की कोशिशें जारी हैं। यह खबर तब आई, जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने इस हफ्ते तेहरान में ईरान के प्रमुख अधिकारियों के साथ आमने-सामने बैठक की। पाकिस्तानी सरकारी सूत्रों ने शनिवार को अनादोलू को बताया कि अमेरिका और ईरान की टीमों सोमवार को ही पाकिस्तान की राजधानी में अपने तकनीकी-स्तर के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत का दूसरा दौर शुरू कर सकती हैं। सूत्रों ने बताया कि दोनों विरोधी पक्षों के वार्ताकार 11-12 अप्रैल को

## ‘प्र.मंत्री ...

करते हुए श्रीराम कॉलोनी-बी योजना बनाई। साल 1990 में इस भूमि का अधिग्रहण कर आवासन मंडल को सौंपी गई। इस दौरान समिति ने जेडीए से नियमितकरण कराया। इसके बाद पहले चरण का विवाद हाईकोर्ट और पर अदालत ने साल 2002 में जेडीए को पट्टे जारी करने को कहा और मामला साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट से तय हुआ। इस दौरान साल 2019 में आवासन मंडल ने नई याचिका दायर कर कहा कि साल 2002 का आदेश गलत तथ्यों पर आधारित था। उधर राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ से अपने पक्ष में फैसला आने के बाद राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड ने अवापन/शुद्ध जमीन का पुनः कब्जा लेने की तैयारियां शुरू कर दीं। गत 16 अप्रैल

को आवासन मंडल की टीम मौके पर जे.सी.बी. मशीनों और भारी पुलिस जवानों के साथ तोड़फोड़ शुरू की। यहां जेसीबी मशीन से जमीन पर बनी बार्डरों को तोड़ दिया और अन्य अतिक्रमणों के निर्माण को तोड़ना शुरू किया तो वहां रहने वाले कुछ लोगों ने विरोध जताया और हंगामा कर दिया। इस बीच वहां मौजूद कुछ महिलाओं ने जेसीबी पर पत्थर फेंक दिए। इससे चबराए हाउसिंग बोर्ड अधिकारियों ने कुछ समय के लिए कार्रवाई रोक दी थी। अब श्रीराम कॉलोनी विकास समिति की ओर से दायर अपील पर राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस.पी.शर्मा तथा जस्टिस सुभा मेहता की खंडपीठ के समक्ष शोभा को होगी। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी।

(प्रथम पृष्ठ का शेष) सीधे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के मतदाताओं से सीधे बात करने का अवसर दिया गया। प्रश्न उठता है कि क्या यह मंडल को ऑफ कंडक्ट है या मोदी कंडक्ट ऑफ कंडक्ट? क्या विपक्ष को जवाब देने का ऐसा ही अवसर मिलेगा? बहुत कम संभावना है, क्योंकि यह पूरी तरह मोदी शो है। यह भाषण झूठ, असत्य, अतिशयोक्ति और भाजपा को “पवित्र” और विपक्ष को “दुष्ट” के रूप में पेश करने के प्रयास से भरा था। आम धारणा यह है कि संसद में पहली बड़ी पराजय मिलने के बाद मोदी फिफल रहे हैं। और उनका विपक्ष में सबसे ज्यादा जहद कांग्रेस पार्टी के लिए आरक्षित है।

## इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर आदेश बदला

लखनऊ, 18 अप्रैल। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता मामले में एफआईआर दर्ज करने संबंधी अपने ही आदेश को बदल दिया है। कोर्ट ने शनिवार को अपनी वेबसाइट पर संशोधित आदेश जारी किया। शुक्रवार (17 अप्रैल 2026) को न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकलपीठ

## संशोधित आदेश में दोहरी नागरिकता पर एफआईआर से पहले नोटिस देना जरूरी बताया।

ने याचिका की सुनवाई की। याचिकाकर्ता समेत, केन्द्र और राज्य सरकार के वकीलों से कोर्ट ने पूछा कि क्या राहुल गांधी को नोटिस जारी करने की जरूरत है? सभी पक्षों ने नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं बताई। इसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया था। हालांकि, आदेश के टाइप होने से पहले न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने फैसले की फिर से समीक्षा की।

## ‘विपक्ष ने देश की महिलाओं के सपनों को कुचल दिया’

### प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं होने का दोषी विपक्ष को ठहराया

नई दिल्ली, 18 अप्रैल। महिला आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने आज (शनिवार को) देश को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने इस अहम मुद्दे पर अपना पक्ष रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में महिला सशक्तिकरण, उनकी सियासत में भागीदारी और विपक्ष द्वारा महिला आरक्षण बिल के समर्थन न किये जाने का जिक्र किया। साथ ही, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सही वक्त का इंतजार कीजिए, आधी आबादी को उनका हक दिलाने का संकल्प जरूर पूरा होगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज मैं अपनी बहनों और बेटियों से बात करने के लिए आया हूँ। आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति को उड़ान को रोक दिया गया। उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पास नहीं हो पाया। मैं इसके लिए सभी माताओं-बहनों से क्षमाप्रार्थी हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष ने नारी हित का प्रस्ताव गिरा दिया। विपक्ष

## प्र.मंत्री मोदी ने कहा कि उनका इरादा पक्का है और महिला आरक्षण की राह में आने वाली हर अड़चन वे दूर करेंगे।

ने महिलाओं के सपनों को कुचल दिया। मैं देश की महिलाओं से माफी मांगता हूँ। नारी सबकुछ भूल जाती है, लेकिन अपना अपमान नहीं भूलती है। विपक्ष को मैं कहना चाहता हूँ कि 21वीं सदी की नारी हर घटना पर नज़र रख रही है और सच्चाई भी भली-भाँति जान रही है।

पीएम मोदी ने आगे कहा, हमारे लिए देशहित सर्वोपरि है। लेकिन जब कुछ लोगों के लिए दलित सब कुछ हो जाता है, दलित देशहित से बड़ा हो जाता है तो नारी शक्ति को, देशहित को, इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इस बार भी यही हुआ है। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान

देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थीं। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर वे लोग मेजें थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया, वो केवल डेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी।

मोदी ने कहा, नारी सब भूल जाती है, लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती। इसलिए संसद में कांग्रेस और उसके सहयोगियों के व्यवहार की कसक हर नारी के मन में हमेशा रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि परिसीमन को लेकर कांग्रेस ने झूठ फैलाया। परिसीमन होता तो सभी राज्यों की सीटें एक अनुपात में बढ़तीं, वहीं, समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण विरोधी पार्टी है। सपा ने राममनोहर लोहिया को भुला दिया है। सपा ने लोहिया के सपनों को अपने पैरों तले रौंद दिया। साथ ही, कांग्रेस एंटी-रिफॉर्म पार्टी है। कांग्रेस निरिधित पॉलिटिक्स करती है।

## विपक्ष की एकता ने लोकतंत्र को बचाया

### प्रियंका गांधी ने प्रैस वार्ता में यह भी कहा कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने की साजिश विपक्ष की एकता से नाकाम हुई है।

नई दिल्ली, 18 अप्रैल। महिला आरक्षण विधेयक संसद में पारित न होने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केन्द्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने लोकतंत्र की रक्षा की है और परिसीमन से जुड़ी साजिश को विफल कर दिया है।

कांग्रेस मुख्यालय में शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में प्रियंका गांधी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने महिला आरक्षण कानून पर तीन साल तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया और हाल ही में जल्दबाजी में अधिसूचना जारी की। उन्होंने मांग की कि पहले के स्वरूप में महिला आरक्षण बिल को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, शुक्रवार को लोकतंत्र की बड़ी जीत हुई है। केन्द्र सरकार ने लोकतंत्र को कमजोर करने और संघीय ढाँचे में बदलाव की कोशिश की, जिसे

## प्रियंका गांधी ने कहा महिला आरक्षण की आड़ में सरकार परिसीमन में मनमानी करना चाहती थी।

विपक्ष ने मिलकर नाकाम कर दिया। यह संविधान और देश की जीत है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर बिल पास करवाकर परिसीमन में मनमानी करना चाहती थी और जातिगत जनगणना से बचना चाहती थी। उनके अनुसार, यदि बिल पारित होता तो सरकार इसे अपनी उपलब्धि बताती और यदि नहीं होता तो विपक्ष को महिला विरोधी करार देती। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं से जुड़े कई गंभीर मामलों, उनाव, हाथरस, मंहिला खिलाड़ियों और मणिपुर की घटनाओं में सरकार का रवैया उदासीन रहा है। अब वही सरकार खुद को महिलाओं का हितैषी दिखाने

की कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी ने स्पष्ट किया कि यह केवल महिला आरक्षण का मुद्दा नहीं था, बल्कि परिसीमन और राजनीतिक संतुलन से भी जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस तरह के प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता था, जिसमें सरकार को बिना पारदर्शिता के फैसले लेने की छूट मिलती हो। उन्होंने यह भी कहा कि देश ने देख लिया है कि जब विपक्ष एकजुट होता है, तो केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार को चुनौती दी जा सकती है। यही कारण है कि सरकार इस दिन को ‘ब्लैक डे’ बता रही है, जबकि विपक्ष इसे लोकतंत्र की जीत मानता है। कांग्रेस महासचिव ने अंत में कहा कि देश की महिलाएं अब जागरूक हैं

और सरकार की पीआर और मीडियाबाजी को समझ रही है।

## एसआई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) सजा सभी को देना उचित नहीं है। याचिका में कहा गया कि चर्चयित एसआई ने कठोर मेहनत से इस परीक्षा को पास किया है और अब इस स्तर पर उन्हें भर्ती से बाहर करना सही नहीं है। चर्चयित एसआई की एसएलपी पर आगामी दिनों में सुनवाई होने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर भर्ती में चयन से निराश रहे और भर्ती रद्द करवाने वाले अभ्यर्थियों ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी है, जिससे कि चर्चयित अभ्यर्थियों की एसएलपी में कोई भी आदेश देने से पहले सुप्रीम कोर्ट उनका पक्ष भी सुनेगा।

## ‘कैसे ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) हाथियों की संख्या भी बढ़ती गई। याचिका में कहा गया कि स्पष्ट नियम होने के बावजूद, अनाधिकृत और बाहरी लोग आमेर किले और हाथीगंज के बाहर हाथी सवारी करा रहे हैं। इसके बदले पर्यटकों से पांच हजार से दस हजार रुपये से वसूल जा रहे हैं। याचिका में कहा गया कि उनकी ओर से संबंधित अधिकारियों को कई बार लिखित शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते निर्धारित क्षेत्रों के बाहर हाथी सवारी कराई जा रही है। याचिका में गुहार की गई है कि अवैध हाथी सवारी पर पाबंदी लगाई जाए और अनाधिकृत लोगों को हाथी सवारी कराने से रोका जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

## केन्द्रीय ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) प्रतिशत में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। यह वृद्धि एक जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। इस फैसले से लगभग 50.46 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों और 68.27 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। डीए और डीआर में इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना 6791.24 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह नियम सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा सुझाए गए स्वीकृत फॉर्मूले के अनुरूप है।

## मोजतबा खामनेई ने सेना के नाम संदेश प्रसारित किया

### ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा बिजली की तरह हमला करो

तेहरान, 18 अप्रैल। ईरान में आर्मी डे के मौके पर सुप्रीम लीडर मोजतबा खामनेई ने सेना को लेकर बड़ा और सख्त संदेश दिया है। उन्होंने हाल ही में हुए 40 दिन के युद्ध के दौरान सेना की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि ईरान की सेना ने दुश्मनों के खिलाफ साहसिक रक्षा की और उन्हें करारा जवाब दिया। सुप्रीम लीडर बनने के बाद यह उनका पहला आर्मी डे संबोधन था, जिससे इस बयान को और ज्यादा अहम माना जा रहा है।

मोजतबा खामनेई ने अपने संदेश में कहा कि ईरान की सेना को अब और मजबूत बनाना जरूरी है और उसे बिजली की तरह वार करने की क्षमता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हालिया युद्ध ने दुश्मनों की कमजोरी और हार को उजागर कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि सेना की ताकत बढ़ाने के लिए जल्द ही नए कदम उठाए जाएंगे।

सुप्रीम लीडर ने खास तौर पर सेना की तकनीकी ताकत, ड्रोन क्षमता और नौसेना की भूमिका को सराहा। उन्होंने कहा कि ईरान के ड्रोन दुश्मनों पर बिजली की तरह हमला करते हैं और नौसेना किसी भी समय दुश्मनों को हराने के लिए तैयार है। उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले

## उन्होंने ईरान -अमेरिका वॉर, जिसमें अभी युद्ध विराम है, पर कहा, हमने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया है यह युद्ध हमारी सेना की ताकत को साबित करता है।

समय में इन क्षेत्रों को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने हाल ही में खत्म हुए 40 दिन के युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान की सेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड ने मिलकर दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचाया। यह युद्ध 8 अप्रैल को युद्धविराम के साथ खत्म हुआ था। उन्होंने इसे एक बड़ी जीत बताते हुए कहा कि इसने ईरान की सैन्य ताकत को साबित किया है। मोजतबा खामनेई ने इस मौके पर युद्ध में जान गंवाने वाले कमांडरों और सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी। उन्होंने कहा कि इन सैनिकों के बलिदान की वजह से ही देश सुरक्षित है। उन्होंने कई पुराने और हालिया सैन्य नेताओं का नाम लेकर उन्हें याद किया और उनके योगदान को देश के लिए अहम बताया।

## ईरान में भी नेतृत्व में “पावर स्ट्रगल” ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) कि परमाणु रणनीति से लेकर होर्मुज स्ट्रेट तक के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ईरानी रुख अस्पष्ट हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रमित करने वाले बयानों और प्रमुख मुद्दों पर बार-बार रुख बदलने से भी स्थिति जटिल हो गई है। बढ़ते भ्रम में, मैदान पर तैनात सैन्य बल शायद स्थिति को अपनी समझ के अनुसार कार्य कर रहे हैं। स्थिति और गंभीर हो गई है, क्योंकि पूरी ईरानी कमांड संरचना अत्यंत विविधापूर्ण है और ज़मीनी स्तर के कमांडरों को कार्य करने की बहुत स्वतंत्रता है। इस प्रकार, ज़मीनी स्तर पर, सैन्य बलों और आईआरजीसी ने अपनी कार्यवाही जारी रखी, जबकि उच्च स्तर पर नेता सैन्य कार्रवाई को धीमा करने

का इरादा रख रहे हैं। जहाँ ईरानियों ने पहले होर्मुज स्ट्रेट को वाणिज्यिक यातायात के लिए खुला घोषित किया था, वहीं, जब रिवोल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा यह खुलासा किया गया कि अमेरिकी अफी भी ईरानी बंदरगाहों से आने-जाने वाले जहाजों को रोक रहे हैं, तो रुख बदल गया और होर्मुज को बंद कर दिया गया। इन जलमार्गों पर गश्त करने वाले ईरानी गनबोट्स ने उन जहाजों पर गोलीबारी की, जो स्ट्रेट से गुजरने और ओमान की खाड़ी की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। इनमें से एक सुपर-टैंकर भारतीय झंडे वाला था और उस पर भी गोलीबारी हुई, जिसके बाद जहाज वापस मुड़ गया। भारतीय जहाज, सैनमार हेराल्ड,

तेल लेकर, भारत की ओर जा रहा था और अचानक गोलीबारी से चौंक गया। अब तक, भारतीय जहाजों को युद्धविराम के चरण समय में भी स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरने की सुविधा मिली हुई थी। एक अन्य भारतीय जहाज, जग अनंन, को भी आईआरजीसी गार्ड्स द्वारा वापस लौटने का आदेश दिया गया था। घटना के बाद, यह खबर आई कि भारत के विदेश कार्यालय ने ईरान के भारत स्थित राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। यह नहीं पता कि ईरानी विदेश मंत्रालय और सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दी। टी.एस. एलियट ने 1923 में यह लिखा था, अप्रैल साल का सबसे क्रूर महीना होता है। यह बात अप्रैल 2026 में अत्यधिक साकार हो रही है।